

कनाडा तथा अन्य देशों से गेहूँ का आयात

1710. श्री गं० च० शीक्षित : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में कनाडा के हार्ड-कमिश्नर के उस वक्तव्य से सहमत है जो उन्होंने 1 फरवरी, 1970 को एक प्रश्न के उत्तर में रतलाम (मध्य प्रदेश) में दिया था कि इस समय कनाडा भारत को 4 करोड़ डालर की कीमत का गेहूँ उपहार के रूप में दे रहा है और अब भारत को अधिक गेहूँ की आवश्यकता नहीं है ; और

(ख) यदि हाँ, तो भारत का किन देशों से तथा कितनी मात्रा में गेहूँ प्राप्त हो रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सह-कार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्डे) : (क) कनाडा सरकार ने अपने करार में उनके देश से गेहूँ खरीदने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में भारत को 4 करोड़ डालर की सहायता देने का संकेत दिया है। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई औपचारिक करार सम्पन्न नहीं हुआ है। तथापि, जब तक देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आश्चर्यजनकता प्राप्त नहीं कर पाया है, तब तक खाद्यान्नों का कुछ आयात करना आवश्यक है। लेकिन खाद्य उत्पादन में वृद्धि से आयात में धीरे धीरे कमी की जा रही है। मौजूदा अनुमानों के अनुसार 1970-71 के बाद रियायती आयात बन्द कर दिए जाने की आशा है।

(ख) फिलहाल संयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत लगभग 28 लाख मीटरी टन गेहूँ तथा उसी देश से 1 लाख मीटरी टन गेहूँ बाणिज्यिक आधार पर आयात करने के प्रबंध किए जा रहे हैं। आशा है कि फ्रांस द्वारा खाद्य-सहायता के रूप में दिया गया लगभग 35,000 मीटरी टन गेहूँ 1970 में पहुँच जायेगा। 1969 में संघीय जर्मन गणराज्य द्वारा

सहायता रूप में दिए गए 64,000 मीटरी टन गेहूँ में से लगभग 46.8 हजार मीटरी टन गेहूँ की शेष मात्रा 1970 में पहुँच जायेगी। आस्ट्रेलिया से लगभग 50 हजार मीटरी टन गेहूँ बाणिज्यिक आधार पर आयात किया जा रहा है तथा उसी देश से लगभग 68 हजार मीटरी टन गेहूँ (आस्ट्रेलिया द्वारा उपहार रूप में दिए गए 70,000 मीटरी टन का शेष) जनवरी, 1970 में प्राप्त हो गया है। आशा है कि 1970 में मुख्यतः अर्जेंटिना से भी यू० के० द्वारा सहायता रूप में दिया गया 28.8 लाख डालर की लागत का गेहूँ (अथवा कुछ अन्य अनाज—चावल को छोड़कर) आयात किया जायेगा। 1970 में गेहूँ का और आयात भविष्य में किए जाने वाले प्रबन्धों पर निर्भर करेगा।

खाने के तेलों की कीमत में वृद्धि

1711. श्री श्रीगोपाल साहू : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों में देश में खाने के तेल की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में अनेक स्थानों पर खाने का तेल सदा आसानी से उपलब्ध नहीं होता जिसके परिणामस्वरूप आम जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) देश के सभी भागों में उचित कीमतों पर खाने का तेल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाए किए जाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सह-कार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्डे) : (क) जी हाँ। खाने के तेलों के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(ख) - सरकार को खाने के तेलों की